गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 274
दि. 05.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

356 दिन बाद मणिपुर को मिली निर्वाचित सरकार, युमनाम खेमचंद सिंह ने संभाली कमान, सत्ता संतुलन के साथ नई शुरुआत

(जीएनएस)। करीब एक साल तक चले राजनीतिक शून्य और राष्ट्रपति शासन के दौर के बाद मणिपुर में आखिरकार लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हो गई है। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की बागडोर संभाल ली। इंफाल स्थित लोकभवन में आयोजित सादे लेकिन बेहद अहम शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खेमचंद मैतेई समुदाय से आते हैं और ऐसे समय में मुख्यमंत्री बने हैं, जब मणिपुर लंबे जातीय तनाव, अविश्वास और हिंसा के दौर से गुजर चुका है। उनके साथ सत्ता संतुलन और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए नगा समुदाय से लोधी दिखो और कुकी समुदाय से नेमचा किपगेन ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इस शपथ ग्रहण के साथ ही मणिपुर में 356 दिनों से लागू राष्ट्रपति शासन का औपचारिक अंत हो गया। बुधवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी की। गौरतलब है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालात लगातार बिगड़ते चले गए और चार दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद से राज्य प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में रहा और राजनीतिक अस्थिरता मणिपुर की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी।

युमनाम खेमचंद सिंह के नाम पर सहमति बनने की प्रक्रिया भी बेहद अहम मानी जा रही है। 3 फरवरी को

दिल्ली में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें खेमचंद को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। इसके अगले दिन एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लगी। यह फैसला केवल राजनीतिक गणित नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मैतेई समुदाय से मुख्यमंत्री, नगा और कुकी समुदाय से दो उपमुख्यमंत्री—यह संयोजन मणिपुर के हालिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है।

खेमचंद सिंह इंफाल वेस्ट के सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे मणिपुर की राजनीति में कोई नया नाम नहीं हैं। वर्ष 2017 से 2022 तक वे मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और 2022 में एन. बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में मंत्री भी रहे। बीरेन सिंह के करीबी माने जाने के बावजूद उनकी पहचान एक अपेक्षाकृत मध्यमार्गी नेता की रही है। मैतेई समुदाय से आने के बावजूद वे कट्टर रुख के लिए नहीं जाने जाते। मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद दिसंबर 2025 में कुकी बहुल इलाकों और राहत शिविरों का दौरा करने वाले वे पहले मैतेई नेता बने थे। इसी वजह से पार्टी और केंद्र नेतृत्व को उन पर भरोसा है कि वे संवाद और संतुलन के जरिए हालात को संभाल सकते हैं।

नई सरकार में नगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए लोधी दिखो को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। वे नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं और राज्य की पहाड़ी राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं, कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन ने इतिहास रचते हुए मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। खास बात यह रही कि नेमचा ने दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। वे कांगपोकपी सीट से 2017 और 2022 में विधायक चुनी गईं और बीरेन सिंह सरकार में सामाजिक कल्याण, सहकारिता, वाणिज्य और उद्योग जैसे अहम विभागों की कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं।

मैतेई-कुकी हिंसा के दौरान नेमचा किपगेन का इम्फाल स्थित सरकारी आवास जला दिया गया था। वे उन 10 कुकी-जो विधायकों में शामिल रही हैं, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन की मांग उठाई थी। ऐसे में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाना कुकी समुदाय को भरोसे में लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नई सरकार के इस फैसले से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मणिपुर में अब केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि सभी समुदायों की भागीदारी के साथ शासन चलाया जाएगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि युमनाम खेमचंद सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में शांति बहाल करना, विस्थापितों की वापसी और समुदायों के बीच टूटे भरोसे को जोड़ना होगा। करीब एक साल के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर की जनता अब स्थिर सरकार से ठोस फैसलों और जमीन पर बदलाव की उम्मीद कर रही है। नई सरकार के गठन से एक नई शुरुआत तो हुई है, लेकिन यह शुरुआत कितनी मजबूत साबित होगी, यह आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसलों और संवाद की दिशा पर निर्भर करेगा। फिलहाल, मणिपुर में लंबे इंतजार के बाद लोकतंत्र की वापसी को लोग उम्मीद और सतर्कता—दोनों भावनाओं के साथ देख रहे हैं।

जनगणना 2027 में दूसरे चरण में होगी जातिगत गणना, सरकार ने संसद में स्पष्ट किया पूरा रोडमैप

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में लंबे समय से चर्चा और बहस का विषय बनी जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने बताया है कि जनगणना 2027 के दौरान जाति से संबंधित गणना दूसरे चरण में कराई जाएगी। यह दूसरा चरण जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का होगा, जिसमें देश के हर नागरिक से जुड़े जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण एकत्र किए जाएंगे। इस जानकारी के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि जाति आधारित आंकड़े उसी चरण में जुटाए जाएंगे, जिसमें व्यक्ति स्तर की सूचनाएं दर्ज होती हैं।

राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 कराने की मंशा को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे चरण में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, जिनमें जाति से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिए जाने के बाद चरण शुरू होने से पहले अधिसूचित किए जाएंगे। यानी अभी जाति से जुड़े प्रश्नों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसे पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा। सरकार के अनुसार, भारत में जनगणना की प्रक्रिया परंपरागत रूप से दो चरणों में होती है। पहले चरण को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें हर परिवार के घर, आवास की स्थिति, पेयजल, शौचालय, बिजली, ईंधन, संपत्तियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होती है, जिसमें घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि जातिगत गणना इसी दूसरे चरण का हिस्सा होगी।

मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को यह भी बताया कि जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार को तमिलनाडु समेत कई राज्यों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस विषय पर राज्यों और सामाजिक समूहों की ओर से लगातार दबाव और सुझाव दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राजनीतिक दल और राज्य सरकारें जातिगत जनगणना की मांग को जोर-शोर से उठाती रही हैं, ऐसे में सरकार की यह घोषणा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन से जुड़े प्रश्न पहले ही 22 जनवरी को अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसके तहत गणनाकर्ता घर-घर जाकर आवास और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे। वहीं, दूसरे चरण के प्रश्न, जिनमें जाति से जुड़े सवाल भी होंगे, बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जातिगत गणना की रूपरेखा और प्रश्नावली को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

जनगणना 2027 को तकनीक के लिहाज से अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना बताया जा रहा है। सरकार के अनुसार, इस विशाल प्रक्रिया में देशभर में लगभग 30 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक तथा करीब 1.3 लाख जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। इन सभी को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि डेटा संग्रह की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सटीक हो सके। मंत्री ने बताया कि इसके लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और स्व-गणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जा चुके हैं।

सरकार का कहना है कि डेटा की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डेटा संग्रह से लेकर उसके प्रसारण और सर्वर स्तर तक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। मोबाइल एप्स में ऑफलाइन डेटा संग्रह की सुविधा भी होगी, ताकि नेटवर्क की समस्या वाले इलाकों में भी गणना का काम प्रभावित न हो। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कागजी फॉर्म का उपयोग किया जाएगा और ऐसी स्थिति में भी डेटा को चार्ज स्तर पर ही डिजिटाइज कर लिया जाएगा।

ऑनलाइन निवेश के जाल में फंसा करोड़ों का खेल, चार शहरों में फैला ठगी नेटवर्क दिल्ली पुलिस के शिकंजे में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट की इस कार्रवाई को हाल के समय की बड़ी साइबर ठगी के खुलासों में अहम माना जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक रियल एस्टेट डेवलपर से करीब 3.76 करोड़ रुपये की ठगी की थी। इस गिरोह की जड़ें मुंबई, कोटा, नोएडा और लखनऊ तक फैली हुई थीं और इन्हीं शहरों में एक साथ छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा गया।

पुलिस के अनुसार, ठगी का शिकार हुए कृष्ण कुमार एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उन्हें ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में निवेश कर कम समय में भारी रिटर्न मिलने का लालच दिया गया। शुरुआत में आरोपियों ने खुद को अनुभवी निवेश सलाहकार और मार्केट एक्सपर्ट बताकर भरोसा जीता। व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क में रहकर उन्हें फर्जी ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट, मुनाफे के आंकड़े और कथित क्लाइंट्स की सफलता की कहानियां दिखाई गईं। इस

सुनियोजित तरीके से पीड़ित को यह विश्वास दिला दिया गया कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है और जल्द ही कई गुना होकर वापस आएगा।

धीरे-धीरे निवेश की रकम बढ़ाई गई और अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। शुरुआत में छोटे अमाउंट पर कुछ नकली रिटर्न दिखाकर भरोसा और मजबूत किया गया। इसके बाद एक ही झटके में करोड़ों रुपये विभिन्न खातों में डलवा लिए गए। जब पीड़ित ने मुनाफा निकालने की बात कही, तो आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और अंततः संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद कृष्ण कुमार ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामला आईएफएसओ यूनिट को सौंपा गया।

शिकायत मिलते ही साइबर विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों की एक टीम बनाई गई। सबसे पहले उन बैंक खातों की पड़ताल की गई, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। जांच के दौरान एक अहम सुराग तब मिला, जब पता चला कि मुंबई निवासी सिबलू कुमार के नाम पर दर्ज एक बैंक खाते में 10 लाख रुपये जमा कराए गए थे। तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रेल के आधार पर पुलिस ने सिबलू की लोकेशन ट्रेस की, जो उस समय राजस्थान के कोटा में मौजूद था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे कोटा से गिरफ्तार कर लिया।

सिबलू कुमार से पूछताछ के दौरान ठगी के पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। उसने कबूल किया कि वह सिर्फ एक कड़ी है और उसके साथ कई अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जो अलग-अलग शहरों में बैठकर म्यूल अकाउंट्स और फर्जी पहचान के जरिए पैसों का लेनदेन संभालते हैं। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मुरादाबाद निवासी वसीम अहमद तक पहुंच बनाई, जो इस नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था। वसीम को दिल्ली के जंगपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपने तीन साथियों—राजेश खान, शाहिद अली और मन्नू इस्सर—के साथ छिपा हुआ था।

इसके बाद एक और आरोपी मनीष कुमार को दिल्ली के द्वारका इलाके से दबोचा गया। पुलिस का कहना है कि मनीष तकनीकी संचालन और बैंक खातों के प्रबंधन में माहिर था। वह फर्जी सिम कार्ड, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पैसों को इधर-उधर करने में सक्रिय भूमिका निभाता था। गिरफ्तार सभी आरोपियों के पास से कुल नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल ठगी को अंजाम देने और आपसी संपर्क के लिए किया जा रहा था।

इन मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां से कई चौंकाने वाले डिजिटल सबूत सामने आए। जांच में म्यूल बैंक अकाउंट्स की पूरी सूची, फर्जी निवेश ग्रुप्स, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह गिरोह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग-अलग राज्यों में कई लोगों को इसी तरह निशाना बना चुका है। आशंका है कि ठगी की कुल रकम तीन करोड़ से कहीं अधिक हो सकती है।

कंक्रीट के जंगलों में तपता भविष्य शहर बनते जा रहे हैं आग के टापू

(जीएनएस)। दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस रफ्तार की एक भयावह कीमत अब साफ नजर आने लगी है। शहर, जो कभी बेहतर जीवन, रोजगार और सुविधाओं का प्रतीक माने जाते थे, अब धीरे-धीरे भीषण गर्मी के केंद्र बनते जा रहे हैं। हाल ही में यूके की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लिया के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन ने इस खतरे को और भी स्पष्ट कर दिया है। इस शोध के मुताबिक भारत सहित दुनिया के अधिकांश ऊष्णकटिबंधीय शहर 'अर्बन हीट आइलैंड' में तब्दील हो रहे हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में शहरों में रहने वाले लोगों को गांवों की तुलना में दोगुनी गर्मी झेलनी पड़ सकती है।

इस अध्ययन में बताया गया है कि बेतहाशा कंक्रीट निर्माण, ऊंची-ऊंची इमारतें, चौड़ी डामर की सड़कें और हरियाली की लगातार होती कटौती शहरों को एक विशाल हीट ट्रैप में बदल रही हैं। कंक्रीट और डामर दिनभर सूरज की तपिश को सोख लेते हैं और रात में उसे धीरे-धीरे छोड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि शहरों में न तो दिन के समय राहत मिलती है और न ही रातें ठंडी हो पाती हैं। यही वजह है कि गर्मियों में महानगरों और कस्बों में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जबकि आसपास के ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत कम गर्मी महसूस होती है।

रिपोर्ट में खास तौर पर मध्यम आकार के शहरों पर चिंता जताई गई है, जिनकी आबादी तीन लाख से दस लाख के बीच

है। दुनिया भर में ऐसे शहरों की संख्या बड़े महानगरों की तुलना में ढाई गुना अधिक है और वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं शहरों में रहता है। भारत में भी तेजी से बढ़ते ऐसे शहर विकास की दौड़ में हरित क्षेत्रों और जल निकायों की अनदेखी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यही शहर आने वाले समय में सबसे ज्यादा 'हीट स्ट्रेस' का सामना करेंगे, जहां गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा संकट बन सकती है।

ग्लोबल वार्मिंग इस समस्या को और गंभीर बना रही है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि वैश्विक तापमान में आने वाले दशकों में और वृद्धि होती है, तो शहरों में गर्मी का असर ग्रामीण इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक होगा। लगातार बढ़ती गर्मी मानव शरीर की सहनशीलता की सीमा को चुनौती देगी। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हृदय और सांस संबंधी बीमारियों के मामलों में तेज इजाफा हो सकता है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में होंगे।

सैटेलाइट आंकड़ों और जमीनी डेटा के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि भारत जैसे ऊष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के करीब 81 प्रतिशत शहरों में दिन के समय जमीन की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यह बढ़ोतरी केवल मौसम के बदलाव का परिणाम नहीं है, बल्कि शहरी ढांचे में हो रहे स्थायी परिवर्तनों का नतीजा है। पेड़ों की जगह कंक्रीट, तालाबों की जगह इमारतें और खुली जमीन की जगह पार्किंग स्पेस ने शहरों की प्राकृतिक ठंडक छीन ली है।

इस बढ़ती गर्मी का असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा। शहरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा, जिससे बिजली की मांग में भारी उछाल आएगा। पहले से दबाव झेल रहे ऊर्जा ढांचे पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और बिजली कटौती की समस्या और गंभीर हो सकती है। साथ ही, अधिक बिजली उत्पादन का मतलब अधिक कार्बन उत्सर्जन, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करेगा। इस तरह एक खतरनाक चक्र बनता जा रहा है, जहां गर्मी बढ़ती है और उसे कम करने के उपाय ही आगे चलकर गर्मी को और बढ़ा देते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी भी शहरी नियोजन में ठोस बदलाव नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। हरित क्षेत्रों का विस्तार, पुराने तालाबों और नदियों का संरक्षण, छतों पर हरियाली, कूल रूफिंग तकनीक और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री को अनिवार्य बनाना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। शहरों को केवल कंक्रीट के ढेर के रूप में नहीं, बल्कि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना होगा।

यह अध्ययन एक चेतावनी है कि विकास की मौजूदा दिशा अगर नहीं बदली गई, तो शहर सुविधा नहीं बल्कि सजा बन जाएंगे। भारत जैसे देशों में, जहां शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, यह खतरा और भी बड़ा है। सवाल यह नहीं है कि गर्मी बढ़ेगी या नहीं, सवाल यह है कि हम इस बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए अभी कदम उठाते हैं या तब, जब शहर सचमुच आग के टापू बन चुके होंगे।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

टैरिफ में राहत

यह सुखद ही है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाये गए भारी-भरकम पचास फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देने की बात कही जा रही है। दलील दी जा रही थी कि भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने के एवज में पच्चीस फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। कुछ वैश्विक व्यापार के जानकार मानते हैं कि यह व्यापार समझौते को अमेरिका के पक्ष में लाने के लिये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा ही था। लेकिन जिसके आगे भारत ने जल्दी से घुटने नहीं टेके थे। अब कहा जा रहा है कि टैरिफ के पचास फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से भारत ने राहत की सांस ली है। यह भारत के रत्न, आभूषण, वस्त्र और परिधान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिये सुखदकारी खबर है, जो बीते साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद से ही संघर्षरत रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सिरे चढ़ने के करीब है। आशंका जताई जा रही है कि यह समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। हालांकि, इस समझौते से जुड़े व्यापक विवरण का अभी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से पेट्रोलियम पदार्थ, रक्षा संबंधी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार से जुड़े उपकरण और विमानों की खरीद बढ़ाएगा। अमेरिका के नीति-नियंता दलील देते रहे हैं कि यह व्यापार समझौता उसके व्यापार घाटे को कम करने और कथित रूप से भारत को 'अनुचित लाभ' से वंचित करने की डोनाल्ड ट्रंप की मंशा के अनुरूप ही है। यह समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ने दबाव डालकर भारत को रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिये बाध्य कर लिया है। हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। इसी तरह व्यापार बाधाओं को कम करने में भी कुछ वक्त लग सकता है।

वैसे रूस से तेल खरीदने पर रोक के संकेत तब मिलने लगे थे, जब भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी ओर रूस से होने वाली कम आपूर्ति से उपजी परिस्थितियों के मुकाबले के लिये भारत ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ा दिया था। वैसे इस बाबत चिंता की बात तब उत्पन्न हुई थी जब अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने कहा था – 'व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा, कीमतों में वृद्धि करेगा और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में नकदी का प्रवाह बढ़ाएगा।' ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मोदी सरकार डेयरी और कृषि क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिये भारत के बाजारों को खोलते हुए घरेलू किसानों के हितों की रक्षा कर पाएगी? यह जानते हुए भी कि भारत में कृषि व किसान राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा है। वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार दबाव व 'या तो मेरी बात मानो या फिर रास्ता छोड़ दो' वाले रवैये ने नई दिल्ली को कई रियायतें देने और समझौते करने के लिये मजबूर कर दिया है। निस्संदेह,यह एक हकीकत है कि व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका का पलड़ा भारी बना हुआ है। जिससे भारत की सौदेबाजी करने की क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता बनाये रखने की क्षमता को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धियों मसलन इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश आदि पर अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जा रहे हैं। हालांकि, चिंता इस बात को लेकर भी जतायी जा रही है कि भारत ने ट्रंप को मात देने का एक अवसर खोया भी है। वैसे यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका की सारी नीतियां अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पर ही खत्म हो जाती हैं। खासकर ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ये नीतियां ज्यादा आक्रामक रूप में सामने आई हैं। जिसका खामियाज उसके मित्र देश भी भुगत रहे हैं।

भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है

> "उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है।

दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब, इस समझौते की शर्तों को इन देशों की संसद द्वारा पारित किया जाएगा, इसके बाद यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन एवं भारत के बीच होने वाले विदेशी व्यापार पर लागू हो जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते को "मदर आफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है। क्योंकि, यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व के 28 देशों के उस भूभाग पर लागू होने जा रहा है, जहां विश्व की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। पृथ्वी के इस भूभाग पर 200 करोड़ से अधिक नागरिकों का निवास है। इन 28 देशों की संयुक्त रूप से विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी (संयुक्त रूप से) अर्थव्यवस्था (यूरोपीय यूनियन - 22 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) एवं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत - 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले विदेशी व्यापार में इन समस्त देशों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। पूरी दुनिया में 33 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार होता है, इसमें से 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार उक्त 28 देशों द्वारा किया जाता है। उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में पूरी दुनिया की आर्थिक दशा एवं दिशा बदलने की क्षमता है। उक्त व्यापार समझौता को सम्पन्न करने के प्रयास पिछले 18 वर्षों से हो रहे थे। परंतु, कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते इस समझौते को सम्पन्न होने में इतना लम्बा समय लग गया है, अतः यह अब भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के

सम्पन्न होने के पश्चात वर्ष 2032 तक यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों एवं भारत के बीच विदेशी व्यापार के दुगना होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके पूर्व भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया जा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी संभवतः मार्च माह में भारत के दौरे पर आने वाले है और भारत एवं कनाडा के बीच भी कुछ क्षेत्रों में व्यापार समझौता सम्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका मुक्त व्यापार समझौतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है ताकि भारत एवं अन्य समस्त देशों में निवासरत नागरिकों को इन समझौतों से लाभ मिले। यह भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को दर्शाता है। भारत की इस नीति के चलते ही विश्व के कई देश अब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते शीघ्र ही सम्पन्न करना चाह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखाई दे रही है। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते से इस उथल पुथल में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा।

इसे भी पढ़ें: भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस वर्ष का बजट

भारत में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र अतिसंवेदनशील है। क्योंकि, भारत की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत भाग आज भी ग्रामीण इलाकों में उक्त क्षेत्रों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अतः उक्त दोनों क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। हां, भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग जो श्रम आधारित उद्योग हैं, को उक्त मुक्त व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों द्वारा भारत से उक्त उत्पादों के आयात पर आयात ड्यूटी को शून्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत से समुद्रीय उत्पादों के निर्यात पर 26 प्रतिशत का आयात कर लगाया जाता है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने के पश्चात शून्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, वस्त्र एवं परिधान के आयात पर वर्तमान में लागू 12 प्रतिशत के आयात कर को शून्य किया जा रहा है, खिलौना पर लागू 4.7 प्रतिशत के आयात कर को शून्य, जेम्स एवं ज्वेलरी के आयात पर 4 प्रतिशत से शून्य, केमिकल उत्पादों के आयात पर 12.8 प्रतिशत से शून्य, चमड़ा से निर्मित उत्पादों के आयात पर 17 प्रतिशत से शून्य, फर्नीचर उत्पादों के आयात पर 10.7 प्रतिशत से शून्य आयत कर किया जा रहा है।

यूरोपीय यूनियन के 27 देश, जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं, में जन्म दर पिछले कई वर्षों से लगातार गिर रही है एवं कुछ देशों में तो यह शून्य के स्तर पर पहुंच गई है जिससे इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों का इन देशों में नितांत अभाव दिखाई देता है। अतः इन देशों में श्रमबल की भारी कमी है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों में तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आदि में रोजगार के भारी मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। इन समस्त देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। युनाईटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स आदि जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों में भारतीय इंजिनीयरों एवं डाक्टरों की भारी मांग है। उक्त देशों द्वारा भारतीयों के परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करने सम्बंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थियों द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत 9 माह से 12 माह तक का समय रोजगार तलाशने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस समयावधि तक भारतीय युवाओं को इन देशों में प्रवास की अनुमति प्रदान की जाएगी।

भारतीय कारीगरों के लिए अब वैश्विक बाजार खुल रहा है। साथ ही, भारत अब विनिर्माण इकाईयों का वैश्विक केंद्र बन सकता है। क्योंकि, यूरोपीयन यूनियन के समस्त देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं एवं वे अपनी सम्पत्ति/पूंजी का निवेश भारत में विनिर्माण इकाईयों में कर सकते हैं एवं कुछ लाभप्रद क्षेत्रों में वे अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भी कर सकते हैं। अधिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना से भारत में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित होंगे। इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को इस दृष्टि के साथ सम्पन्न किया जा रहा है ताकि इससे भारत के किसान, मजदूर, कारीगर, पेशेवर नागरिकों एवं सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ हो। यूरोपीयन यूनियन के समस्त 27 देशों में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का आकार 26,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, इससे भारत से वस्त्र एवं परिधान का निर्यात वर्तमान में 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार, चमड़ा उत्पादों का बाजार 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जेम्स एवं ज्वेलरी का बाजार 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। 27 देशों में इस विशाल क्षेत्र में भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग एवं अन्य उत्पादों को प्रवेश मिलने से भारत में श्रम आधारित कई सूक्ष्म, छोटी एवं मध्यम इकाईयों को लाभ होने जा रहा है। लगभग इसी प्रकार का लाभ अन्य क्षेत्रों यथा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, खिलोना उत्पाद, जेम्स एवं ज्वेलरी उत्पाद, केमिकल उत्पाद, फर्नीचर उत्पाद आदि, में कार्यरत इकाईयों की भी होने जा रहा है। इन क्षेत्रों में कार्यरत विनिर्माण इकाईयों के व्यापार में वृद्धि का आश्य सीधे सीधे अधिक श्रमबल की आवश्यकता होना भी है, जिसकी पूर्ति आज विश्व में केवल भारत ही कर सकता है।

रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत का अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करने का है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को सुरक्षा के सम्बंध में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी है। अतः यूरोपीय देश अपने सुरक्षा बजट में अत्यधिक वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं। भारत के लिए ऐसे समय पर उक्त मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना एक सुनहरे अवसर के रूप में सामने आया है। इससे सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादन कर रही भारतीय कम्पनियों को यूरोपीय यूनियन का अति विशाल बाजार मिलने जा रहा है। इसी के साथ ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी का हस्तांतरण भारतीय कम्पनियों को सम्भव हो सकेगा। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों के साथ सम्पन्न किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते से भारत के लिए अतिलाभप्रद स्थिति बनने जा रही है।

प्रेरणा

दूसरों के दुख में रोने वाला संवेदनशील हृदय

गोपबंधु दास, जिन्हें पूरा उत्कल 'उत्कल-मणि' के नाम से जानता है, केवल एक शिक्षाविद् या समाजसेवी नहीं थे, वे चलते-फिरते करुणा के जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन दिखावे की सेवा से नहीं, बल्कि मौन तपस्या से बना था। वे मानते थे कि मानवता का असली धर्म पीड़ा में पड़े मनुष्य के साथ खड़ा होना है, चाहे उसके लिए अपनी सुविधा, अपना आराम और अपनी नींद ही क्यों न त्यागनी पड़े। उनके लिए सेवा कोई अवसर नहीं, बल्कि स्वभाव थी। शायद इसी कारण उनके छोटे-छोटे कर्म भी बड़े आदर्श बन गए।

एक बार उनके पड़ोस के एक गांव में भीषण आग लग गई। देखते-देखते कई झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। लोगों की जीवनभर की कमाई, अन्न, वस्त्र, मवेशी और छत—सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। जैसे ही यह समाचार गोपबंधु दास तक पहुंचा, उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वे अपने छात्रों और शिक्षकों को साथ लेकर तुरंत घटनास्थल की ओर चल पड़े। उस समय न कोई सरकारी आदेश था, न कोई औपचारिक राहत अभियान। केवल मनुष्यता की पुकार थी, जिसे सुनकर वे निकल पड़े थे।

आग बुझाने में उन्होंने स्वयं श्रम किया। पानी ढोया, लोगों को सुरक्षित निकाला, घायलों को संभाला और बच्चों को ढाढ़स बंधाया। जिनके घर जल गए थे, उन्हें उन्होंने सांत्वना दी, यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उस दिन सूर्य ढलने तक वे वहां डटे रहे और जब सब कुछ शांत हुआ, तब लौटे। लौटते समय उनके चेहरे पर थकान थी, पर संतोष भी था कि वे यथासंभव मदद कर सके।

दो दिन बीत गए। छात्रावास में जीवन फिर अपने सामान्य क्रम में लौट आया। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। आधी रात के आसपास अचानक तेज आंधी उठी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज़ में जैसे पूरा आकाश रो रहा हो। इसी बीच कहीं से धीमी-सी सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी दबे स्वर में थी कि पहली बार में भ्रम हुआ, पर कुछ ही पलों में वह स्पष्ट हो गई—कोई सचमुच रो रहा था।

छात्रालय में रहने वाले अधेड़ हरिहर दास की नींद सबसे पहले टूटी। वर्षों की साधना और अनुशासन ने उनकी चेतना को सजग बना दिया था। उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज किसी दूर कोने से नहीं, बल्कि पास के ही किसी कमरे से आ रही थी। वे चुपचाप उठे और पांच-छह कमरे पार करते हुए उस कमरे के पास पहुंचे, जहां से सिसकियां आ रही थीं। उन्होंने धीरे-से किवाड़ खटखटाया।

दरवाज़ा खुला तो जो दृश्य सामने था, उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। गोपबंधु दास बैठे हुए रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे किसी बच्चे की पीड़ा उमड़ आई हो। हरिहर दास सहम गए। इतने वर्षों में उन्होंने कभी दास जी को इस तरह टूटते नहीं देखा था। इसी बीच आवाज सुनकर अन्य छात्र भी जाग गए और धीरे-धीरे सब उस कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था—दास जी क्यों रो रहे हैं?

कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। फिर हरिहर दास ने साहस जुटाकर पूछा, "दास जी, आप क्यों रो रहे हैं?" यह प्रश्न सरल था, पर उसका उत्तर साधारण नहीं था। गोपबंधु दास ने आंखें पोंछते हुए गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में पीड़ा और करुणा दोनों घुली हुई थीं। उन्होंने कहा, "हरिहर, मैं यहां छत के नीचे, सूखे बिस्तर पर आराम से लेटा हूं। बाहर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है। दो दिन पहले जिन लोगों के घर उस आग में जल गए थे, वे इस समय कहां होंगे? अपने बाल-बच्चों और पशुओं को लेकर वे किस कोने में शरण ढूंढ रहे होंगे? इसी चिंता ने मेरी नींद छीन ली है।"

उनके शब्द सुनकर वहां खड़े सभी छात्र मौन हो गए। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उस क्षण उन्हें समझ में आया कि सच्ची मानवता क्या होती है। गोपबंधु दास का दुख किसी व्यक्तिगत हानि से नहीं था, बल्कि दूसरों की पीड़ा से उपजा था। वे स्वयं सुरक्षित थे, फिर भी असुरक्षितों के लिए व्याकुल थे। उनका हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़कता था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए धड़कता था, जो संकट में था।

वह रात छात्रों के जीवन में एक अमिट पाठ बन गई। उन्होंने देखा कि करुणा केवल दिन के उजाले में दिखाई देने वाला गुण नहीं है, बल्कि वह अंधेरी रातों में भी जागती रहती है। जब दुनिया सो जाती है, तब भी सच्चा मानवतावादी दूसरों के दुख में जागता रहता है। गोपबंधु दास ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, पर उनके आंसुओं ने वह सिखा दिया, जो बड़े-बड़े ग्रंथ नहीं सिखा पाते।

अगली सुबह दास जी ने फिर उसी गांव की ओर जाने की तैयारी की। इस बार उनके साथ और भी लोग थे, क्योंकि छात्रों के मन में भी वह करुणा जाग चुकी थी। वे समझ चुके थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशील होना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

गोपबंधु दास का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि मानवता प्रेम कोई विचार नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली साधना है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है। आज के समय में, जब संवेदनाएं अक्सर सुविधा के आगे हार जाती हैं, गोपबंधु दास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए रो सकने में है। उनकी वह करुण रात आज भी हमें मौन में पुकारती है—क्या हम भी किसी अनजान पीड़ित के लिए अपनी नींद खोने का साहस रखते हैं?

चुनौतियों के मुकाबले में सक्षम बनें शहर

बजट से पूर्व संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में जिन चुनौतियों ने ध्यान खींचा, उनमें शहरों का समुचित विकास न होना भी सम्मिलित है। आर्थिक विकास का इंजन कहलाने वाले शहर, मात्र आवास न होकर एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना का रूप हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें राष्ट्रीय प्रगति का द्योतक कह सकते हैं, जहां जीवन स्तर उन्नत बनाने की संकल्पना की जाती है।

तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतवर्ष की शहरी आबादी 2024 में लगभग 36.87 प्रतिशत आंकी गई। 2026 के मध्य तक बढ़कर इसके 55.5 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2035 तक यह 67.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। चीन के बाद विश्व में यह दूसरा स्थान होगा किंतु शहरी विकास का वैश्विक स्तर पर जायज़ा लें तो तुलनात्मक तौर पर भारत के अधिकतर शहर पिछड़े नज़र आएंगे।

सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान देने के बावजूद शहरी जीवन अनेकानेक समस्याओं से घिरा है। क्षतिग्रस्त सड़कें, यत्र-तत्र फैली गंदगी में मुंह मारते आवारा पशु, बदबूदार सीवरेज लीकेज, बरसाती जलभराव से जूझते लोग; भारत के बहुतेरे शहरों में यह मंज़र आम देख सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन सुविधाएं नाममात्र। सार्वजनिक सुरक्षा की कमी, जल संकट, अनियंत्रित यातायात से संघर्ष करता जीवन पर्यावरणीय प्रदूषण की मार भी बराबर सहता है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय शहर अपने राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत से भी कम प्राप्त करते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि शहरों का संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा। इसमें सुव्यवस्थित योजना, स्थायी समाधानों, नागरिक भागीदारी, हरित स्थानों, कुशल परिवहन, प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा समावेशी शासन की कमी स्पष्ट झलकती है। आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होने पर भी शहरों में कामगारों की उपलब्धता अथवा उनकी आवासीय सुविधा के प्रति विचारा नहीं जाता। आर्थिकी के केंद्र बनने के बावजूद कई शहर राजनीतिक रूप से हाशिए पर ही रहते हैं, समग्र विकास में यह एक बड़ा अवरोधक है।

दरअसल, शहरों में उत्तरदायी तथा सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिए चार शहरी प्रणालियों पर आधारित ढांचे की आवश्यकता होती है- शहरी नियोजन व डिज़ाइन, शहरी क्षमताएं और संसाधन, सशक्त तथा वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी। किसी भी पक्ष से संबद्ध कोताही समूचे विकास को गड़बड़ा देती है, जबकि हकीक़त में हमारी क़रीब 40 प्रतिशत राज्य राजधानियों में सक्रिय मास्टर प्लॉन का अभाव देखा गया।

अनियोजित व बेतरतीब प्रगति कभी भी ऐच्छिक परिणाम नहीं ला पाती। शहरी विकास अक्सर घनी आबादी की ज़रूरतें पूरी करता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट विकासों और बुनियादी आवास से वंचित शहरी निवासियों की महत्वपूर्ण संख्या के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मूलभूत संरचना में केवल छिटपुट सुधारों को ही विकास का पर्याय मान लेना, शहरी समस्याओं का समूल निराकरण नहीं होने देता। कई नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों, शहरा तथा राज्य के अर्धसरकारी निकायों एवं राज्य विभागों में मौजूदा स्थानिक विखंडन इन शहरों में समूह अर्थव्यवस्थाओं अथवा वायु गुणवत्ता, स्वच्छ जलापूर्ति तथा संरक्षण जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। शहरों में सेवा वितरण और जवाबदेही में सुधार के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना अनिवार्य हो जाता है।

भारतीय शहरों की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, जिससे तीव्र विकास से जुड़ी चुनौतियां अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। बहुत अधिक जनसंख्या शहरीकरण का एक अस्वास्थ्यकर पहलू है जो न केवल शहरी आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, मलिन बस्तियों के विकास पर प्रतिकूल असर डालता है बल्कि बेरोज़गारी, हिंसा, भीड़भाड़ आदि से संबंधित शहरी अराजकता उत्पन्न करने का सबब बन, जीवन की गुणवत्ता भी गिराता है। ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, प्रदूषण जैसी समस्याओं से घिरे शहरों की उत्पादकता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही वहां निवेश की संभावना भी कम हो जाती है। असल में, भारत को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए महानगरीय शासन प्रणाली की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, एक ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो शहर को शासन तथा अर्थव्यवस्था की एक अलग इकाई के रूप में मान्यता दे एवं राजनीतिक जवाबदेही का एकल बिंदु अनिवार्य करते हुए शासन, सेवा वितरण तथा उत्तरदायित्व में स्थानिक और कार्यात्मक विखंडन दूर करे।

सही अर्थों में विकसित शहर वही है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़, पर्यावरण के प्रति जागरूक, सामाजिक रूप से समावेशी एवं अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने वाला हो। आर्थिक सर्वेक्षण में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए जो योजनाएं आरम्भ करने की ज़रूरत बताई गई, उनकी पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को ऐसी रणनीतिक योजना बनानी होगी, जो विकास को सही दिशा दे। योजना व विकास प्रक्रियाओं में नागरिकों की राय व आवश्यकताएं शामिल करने से समाधान टिकाऊ तथा समुदाय-केंद्रित बनेंगे। शहरी स्तर पर हमें सुदृढ़ प्रणालियों तथा संस्थानों की आवश्यकता है, जो विभिन्न राज्यों और ज़िलों के संदर्भों तथा समुदायों के अनुकूल उत्तरदायी शासन प्रदान करके समृद्धि ला सकें।

अभियान

जहां भस्मासुर से बचने को महादेव ने रची लीला, आस्था और रहस्य से घिरी शिवखोड़ी गुफा की अमर कथा

भारत की आध्यात्मिक चेतना केवल ग्रंथों और मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पर्वतों, नदियों, वनों और गुफाओं में भी सांस लेती है। इन्हीं दिव्य स्थलों में एक अत्यंत रहस्यमयी और श्रद्धा से परिपूर्ण स्थान है जम्मू-कश्मीर की शिवखोड़ी गुफा, जिसे लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि स्वयं भगवान शिव ने यहां भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। सामान्य धारणा यह है कि भगवान शिव आज भी अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय उनके साथ विराजमान हैं। किंतु जम्मू क्षेत्र के लोगों की आस्था कुछ और ही कहानी कहती है। उनके अनुसार महादेव केवल कैलाश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे यहां शिवखोड़ी गुफा में भी साक्षात रूप से विद्यमान हैं।

जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर दूर ऊधमपुर जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित यह गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, भय, रहस्य और चमत्कार का अद्भुत संगम है। शिवखोड़ी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई सामान्य गुफा नहीं, बल्कि धरती के गर्भ में बनी एक लंबी सुरंग हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा का दूसरा छोर सीधे अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। यद्यपि आज तक कोई इस मार्ग की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन विश्वास की दुनिया में यह कथा उतनी ही सजीव है जितनी सदियों पहले रही होगी। यही कारण है कि शिवखोड़ी को अमरनाथ के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है।

इस गुफा को लेकर सबसे अधिक चर्चा उस मान्यता की होती है, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति गुफा के भीतर पूरी तरह प्रवेश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। इसी कारण श्रद्धालु गुफा के अंदर बहुत अधिक आगे तक जाने का साहस नहीं करते। दर्शन करने वाले भक्त गुफा के प्रवेश क्षेत्र तक ही रुकते हैं और वहीं भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में साधु-संत इसी गुफा के माध्यम से बाबा अमरनाथ की यात्रा किया करते थे, लेकिन कलियुग में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, जो इस रहस्यमयी मार्ग पर चलने का साहस कर सके।

शिवखोड़ी गुफा की एक और विशेषता इसे और अधिक दिव्य बना देती है। यहां स्थित शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह चट्टानों के प्राकृतिक आकार से स्वयं प्रकट हुआ है। जैसे अमरनाथ गुफा में बर्फ से शिवलिंग बनता है, वैसे ही यहां पत्थर की आकृति ने शिवलिंग का स्वरूप ले लिया है। भक्त इसे स्वयंभू शिवलिंग मानते हैं और पूरे श्रद्धाभाव से इसकी पूजा करते हैं। यही नहीं, गुफा के भीतर

प्राकृतिक रूप से बनी नंदी की आकृति, माता पार्वती के स्वरूप जैसी चट्टानें और छत पर उभरी हुई सर्पाकार आकृतियां इस विश्वास को और गहरा कर देती हैं कि यह स्थान केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम है।

लगभग 200 मीटर लंबी यह गुफा कहीं मात्र 1 मीटर चौड़ी है तो कहीं इसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक पहुंच जाती है। भीतर प्रवेश करते ही ठंडक का अनुभव होता है और वातावरण में एक अलग ही रहस्यमय ऊर्जा महसूस होती है। हल्की रोशनी में जब चट्टानों पर बनी आकृतियां दिखाई देती हैं, तो मन स्वतः ही भक्ति और विस्मय से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो यह स्थान समय और संसार के कोलाहल से कटकर किसी अन्य लोक में स्थित हो।

शिवखोड़ी गुफा से जुड़ी पौराणिक कथा इसे और भी अलौकिक बना देती है। कथा के अनुसार भस्मासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजी ने उसे वरदान दे दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह तुरंत भस्म हो जाएगा। शिवजी उस समय असुर की कुटिल मंशा से अनजान थे। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को यह वरदान मिला, उसका अहंकार जाग उठा और उसने स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया।

भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागना पड़ा। कहा जाता है कि इसी क्रम में महादेव एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और वहां एक गुफा का निर्माण कर उसमें छिप गए। यही गुफा आगे चलकर शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भस्मासुर लगातार उनका पीछा करता रहा, लेकिन जब शिवजी उसकी पकड़ में नहीं आए, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया और नृत्य में लीन हो गया। नृत्य के दौरान मोहिनी ने ऐसी मुद्राएं बनाईं, जिनकी नकल करते हुए भस्मासुर अपने वरदान को भूल गया और उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। उसी क्षण वह अपने ही वरदान के कारण भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा हुई और शिवखोड़ी गुफा उनकी लीला और संरक्षण का साक्षी बन गई। तभी से इस गुफा को भगवान शिव की शरणस्थली और उनकी साक्षात उपस्थिति का प्रतीक माना जाने लगा।

आज भी शिवखोड़ी गुफा में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कोई रोग मुक्ति की कामना लेकर आता है, कोई संतान सुख की प्रार्थना करता है, तो कोई जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने की आशा लेकर यहां शीश नवाता है। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि जो भी सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवखोड़ी में मन्नत मांगता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं।

शिवखोड़ी गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आस्था, पौराणिक चेतना और रहस्यात्मक विश्वासों की जीवंत धरोहर है। यह स्थान यह सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों या पर्वतों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे वहां निवास करते हैं जहां भक्त की श्रद्धा उन्हें बुला लेती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर मान. मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर से आई भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया केवल एक औपचारिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर पेश करती है जो आज विश्व मंच पर आत्मविश्वास, सामर्थ्य और स्पष्ट दृष्टि के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह इस समझौते को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व से जोड़ते हुए "नए भारत की शक्ति" का परिचय बताया है, उससे स्पष्ट होता है कि यह डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापारिक आंकड़ों या टैरिफ दरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति, कूटनीतिक परिपक्वता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह रेखांकित किया कि भारत और अमेरिका के बीच हुई यह ट्रेड डील केवल उद्योगों के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के हित में नए अवसरों के सृजन का माध्यम भी है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और संरक्षणवाद जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, ऐसे समय में दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक साथ आगे बढ़ना अपने-आप में एक सकारात्मक संकेत है। यह साझेदारी यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर वैश्विक कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री के वक्तव्य में यह भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती है कि यह ट्रेड डील भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते केवल रणनीतिक या रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, स्टार्टअप और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से जुड़े हैं। इस समझौते से इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को एक नया आयाम मिलेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच भरोसे का स्तर और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" के विजन को मुख्यमंत्री ने इस डील से मिलने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी टैरिफ का घटकर 18 प्रतिशत होना कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई, निर्यातक और उससे जुड़े लाखों कामगारों के लिए यह एक नई उम्मीद लेकर आएगा। जब निर्यात बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस तरह यह समझौता आर्थिक विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस व्यापार समझौते से उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजारों के नए द्वार खुलेंगे। आज का भारत केवल कच्चा माल या पारंपरिक उत्पाद निर्यात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नवाचार, तकनीक और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे बड़े और परिष्कृत बाजार तक आसान पहुंच भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल पूंजी निवेश बढ़ेगा, बल्कि तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुजरात पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में गुजरात की अग्रणी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। भारत-अमेरिका के इस ऐतिहासिक समझौते से इन सभी क्षेत्रों के उत्पादों के निर्यात को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सीधा लाभ गुजरात के उद्योगों, एमएसएमई इकाइयों और व्यापारिक समुदाय को मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि इस समझौते से भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, भारत का एक मजबूत आर्थिक भागीदार के रूप में उभरना न केवल देश के लिए, बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। अमेरिका के साथ इस तरह का व्यापारिक सहयोग भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देगा।

श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और नागरिक-केंद्रित कूटनीति की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी दृष्टिकोण के कारण भारत-अमेरिका संबंध केवल सरकारी या कूटनीतिक स्तर तक सीमित न रहकर आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि को गति देने में ऐसे समझौतों की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि आर्थिक सहयोग अक्सर राजनीतिक स्थिरता और आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है।

अपने वक्तव्य के अंत में मुख्यमंत्री ने गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बधाई दी। यह बधाई केवल एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि उस भरोसे की अभिव्यक्ति है जो देश और राज्य की जनता को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील आने वाले वर्षों में किस तरह भारतीय उद्योग, रोजगार, नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, यह समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह समझौता नए भारत की उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें देश आत्मनिर्भरता के साथ-साथ विश्व के लिए भी एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार बनकर उभर रहा है।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान",जन जागरूकता अभियान में एम्बुलेंस 108 टीम की सक्रिय सहभागिता

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" जन जागरूकता अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। यह अभियान प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 04 फरवरी 2026 (बुधवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर एक प्रभावी जन जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एम्बुलेंस 108 के हेड श्री कपिल सोलंकी एवं उनकी टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान भावनगर मंडल की कल्चरल टीम एवं स्काउट एवं गाइड की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों एवं स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर एम्बुलेंस 108 की टीम ने एंबुलेंस में उपलब्ध जीवनरक्षक उपकरणों की विस्तृत जानकारी दी तथा आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में बिना किसी हिचक के 108 सेवा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। टीम द्वारा समय पर एम्बुलेंस बुलाने की प्रक्रिया, दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं प्राथमिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गईं।

कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन ऐप (RailOne App) की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यात्रियों को ऐप के प्रमुख लाभों जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया एवं डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की कि वे सदैव उचित टिकट लेकर यात्रा करें तथा इस संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियानों से यात्रियों में रेलवे नियमों, नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा एवं सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

यात्रियों की सुविधा के लिए एकतानगर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा एकतानगर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के समय मे परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का परिवर्तित समय का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 09410 एकतानगर-अहमदाबाद स्टीम हेरिटेज स्पेशल (द्वि-साप्ताहिक) 14.02.2026 से एकतानगर स्टेशन से 20:20 बजे की बजाय अब 20:30 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 20950 एकतानगर - अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस 09.02.2026 से एकतानगर स्टेशन से 20:55 बजे की बजाय अब 20:50 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन नं 69206 एकतानगर - प्रतापनगर मेमू के संचालन समय में जो 10.02.2026 से परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन का एकतानगर स्टेशन पर 22.35 बजे के बजाय 21.05 बजे रवाना होगी। चांदोद स्टेशन पर 22.59/23.00 बजे के बजाय 22.14/22.15 बजे पहुंचेगी/रवाना होगी। डभोई स्टेशन पर 23.18/23.20 बजे के बजाय 22.33/22.35 बजे पहुंचेगी/रवाना होगी। प्रतापनगर स्टेशन पर 00.05 बजे के बजाय 23.15 बजे पहुंचेगी।

यात्री इस ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मण्डल ने अप्रैल 2025 से जनवरी, 2026 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया ₹25.72 करोड़ से अधिक का जुर्माना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों के माध्यम से 25.72 करोड़ से अधिक का जुर्माना प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल अपने यात्रियों की सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है और वैध यात्रियों की सुरक्षित एवं सुखद यात्रा सुनिश्चित करने हेतु अनेक सशक्त कदम उठा रहा है।

अनाधिकृत यात्रा की रोकथाम के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी एवं अन्य वाणिज्य अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन टिकट जांच कार्य की समीक्षा की गई तथा उनके मार्गदर्शन में विशेष टिकट जांच अभियान संचालित किए गए। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में कार्यरत अत्यंत प्रेरित टिकट चेकिंग टीम द्वारा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान अनेक अभियान चलाए गए, जिनके परिणामस्वरूप 25.72 करोड़ की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 54% अधिक है। केवल जनवरी 2026 माह में ही बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं, 32,330 प्रकरणों की पहचान कर 2.48 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से 18% अधिक है।

दिनांक 04.02.2026 को मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री जयेश मकवाना के नेतृत्व में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत 14702 अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, 79434 साबरमती–पाटन डेमू, 79432 साबरमती–महेसाणा डेमू, 79436 पाटन–साबरमती डेमू तथा 12547 आगरा कैंट–साबरमती एक्सप्रेस में सघन जांच की गई। इस अभियान में 10 टिकट जांच स्टाफ एवं 4 आरपीएफ स्टाफ की उपस्थिति रही। अभियान के दौरान बिना टिकट के 120, उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले 19, बिना बुक सामान का 1 तथा गंदगी फैलाने/थूकने के 4 प्रकरण सहित कुल 144 प्रकरण पकड़े गए, जिनसे 47,010 की वसूली की गई। यह अभियान साबरमती–महेसाणा एवं पाटन–साबरमती रेलखंडों में संचालित किया गया।

इस प्रकार के परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल अपने यात्रियों से विनम्र अनुरोध करता है कि वे उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, जिससे उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित एवं आनंददायक हो।

एलसी संख्या 95 पर आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु अस्थायी यातायात परिवर्तन

(जीएनएस)। भावनगर मंडल के अंतर्गत साबरमती–बोटाद रेल खंड में स्थित लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 95 पर आवश्यक बड़े मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाने हैं। इस कार्य के कारण सड़क यातायात को दिनांक 05 फरवरी 2026 को रात्रि 20.00 बजे से 06 फरवरी 2026 को सायं 17.00 बजे तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान यात्रियों एवं वाहन चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था

बगोदरा से धंधुका की ओर जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्गः

बगोदरा – अरणेज – जवारज – गुंदी से फेदरा होकर धंधुका।

धंधुका से बगोदरा की ओर जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्गः

धंधुका से फेदरा और फेदरा से गुंदी गाँव होकर अरणेज और बगोदरा।

पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल आम जनता से अपील करता है कि वे असुविधा से बचने हेतु निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सहयोग प्रदान करें।

यह कार्य यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसके लिए जनता से सहयोग की अपेक्षा है।

गांधीग्राम–भावनगर ट्रेन में छूटा यात्री का बैग वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की तत्परता से सुरक्षित मिला

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के कर्मचारी अपने सम्मानित यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 04 फरवरी, 2026 (बुधवार) को एक यात्री ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम–भावनगर स्पेशल से धोला स्टेशन तक यात्रा कर रहा था। धोला स्टेशन पर उतरने के पश्चात तथा ट्रेन के प्रस्थान के बाद यात्री को यह ज्ञात हुआ कि उसका एक सुटकेस ट्रेन में ही छूट गया है। उक्त सुटकेस में लगभग 21,000/- मूल्य का एक मोबाइल फोन, 1,00,000/- मूल्य की सोने की बुटी, 25,000/- नकद (Cash), नए कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामान रखा हुआ था।

यह सुटकेस ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक–भावनगर श्री एस. डी. गोहिल को लावारिस अवस्था में मिला। इधर, यात्री तुरंत सड़क मार्ग से भावनगर टर्मिनस पहुंचा और स्टेशन पर अपने छूटे हुए सुटकेस के संबंध में जानकारी दी। आवश्यक पूछताछ एवं पहचान सत्यापन के उपरांत सुटकेस को यात्री को सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया।

अपना सामान सही-सलामत प्राप्त होने पर यात्री ने रेल प्रशासन एवं सभी संबंधित कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया तथा कहा कि भावनगर मंडल अपने यात्रियों की सुरक्षा, सेवा और विश्वास बनाए रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

श्री सहर्ष बाजपाई ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। भारतीय रेल कार्मिक सेवा (IRPS) के 1999 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री सहर्ष बाजपाई ने मंगलवार, 03 फ़रवरी 2026 को पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री बाजपाई भारतीय रेल में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कार्मिक संबंधी पदों पर कार्य कर चुके हैं। आपने उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे, मध्य रेल तथा महाराष्ट्र मेट्रो में प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन किया है। आपके द्वारा संभाले गए उल्लेखनीय पदों में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, पुणे; अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मध्य रेल; उप मुख्य कार्मिक अधिकारी; अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, पुणे; महा मेट्रो में महाप्रबंधक (मानव संसाधन); तथा मध्य रेल में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी शामिल हैं। श्री सहर्ष बाजपाई ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर (MPA) की डिग्री प्राप्त की है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन तथा नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। अपने करियर के दौरान आप मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को सुदृढ़ करने, कार्मिक प्रशासन में सुधार लाने तथा कर्मचारी-केंद्रित शासन पद्धतियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। फील्ड इकाइयों एवं मुख्यालय स्तर पर आपके व्यापक अनुभव ने आपको कार्मिक प्रबंधन के प्रति संतुलित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया है। श्री बाजपाई ने INSEAD, सिंगापुर; ICLIF, मलेशिया; KOTI, दक्षिण कोरिया; तथा SWJTU, चीन जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

हापा - नाहरलगून स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित

(जीएनएस)। रतलाम। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर परिचालित गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल की सेवाओं का विस्तार किया गया है।

गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल को पहले 25 फरवरी 2026 तक तथा गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल को 28 फरवरी 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब बढ़ाते हुए दोनों दिशाओं में अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल हापा से 04 मार्च 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक एवं इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल नाहरलगून से 07 मार्च 2026 से 02 जनवरी 2027 तक अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस समय में आंशिक बदलाव

(जीएनएस)। रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से गुजरने वाली अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस का अहमदाबाद एवं दरभंगा से प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। विवरण इस प्रकार है –

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 19165 अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस –06 फरवरी, 2026 से अहमदाबाद स्टेशन से 19.15 बजे के स्थान पर 19.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसीप्रकार गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा - अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस –01 अप्रैल 2026 से यह ट्रेन दरभंगा स्टेशन से 04.30 बजे के स्थान पर 04.20 बजे प्रस्थान करेगी। अन्य स्टेशनों पर इसके आगमन/प्रस्थान समय में कोई बदलाव किया गया।

यात्रीगण कृपया कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में श्री जतिन ठक्कर को शपथ दिलाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात विद्युत नियामक आयोग (जीईआरसी-जर्क) के सदस्य के रुप में नियुक्त किए गए श्री जतिन ठक्कर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर जर्क के अध्यक्ष श्री पंकज जोषी, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री राजेंद्र सरीन और विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों सहित वरिष्ठ सचिव और अधिकारी मौजूद रहे।

कोयंबत्तूर – जयपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित

(जीएनएस)। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कोयंबत्तूर – जयपुर के फेरों को पुनः विस्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 06181 कोयंबत्तूर–जयपुर स्पेशल दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कोयंबत्तूर से प्रति गुरुवार को प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 06182 – जयपुर –कोयंबत्तूर स्पेशल दिनांक 22 फरवरी 2026 तक जयपुर से प्रति रविवार को प्रस्थान करेगी। यात्रीगण ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण इंदौर–शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम। उत्तर रेलवे में निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी । ब्लॉक कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से संचालित होने वाली इंदौर–शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर-इंदौर एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 मई 2026 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22941 इंदौर - शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा जालंधर कैंट से शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार 27 मई 2026 तक शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22942 शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर - इंदौर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा शहीद कैप्टन तुषार महाजन इंदौर उधमपुर से जालंधर कैंट तक निरस्त रहेगी। ट्रेनों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर–ओखा एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित कोच की सुविधा 31 मई 2026 तक विस्तारित

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन (19209/19210) में अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (थर्ड एसी) कोच की सुविधा को 31 मई 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस में एक थर्ड एसी कोच भावनगर टर्मिनस स्टेशन से दिनांक 05 फरवरी 2026 से 31 मई 2026 तक लगाया जाएगा। वहीं ओखा स्टेशन से यह कोच दिनांक 06 फरवरी 2026 से 01 जून 2026 तक संचालित रहेगा।

उक्त ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारिणी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

हादसा, आत्महत्या या साजिश हत्या, शाजापुर में राजेश मालवीय की मौत ने खड़े किए कई सवाल

(जीएनएस)। शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक युवक का शव नदी में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। दुपाड़ा मार्ग स्थित रागवेल की पुलिया के नीचे नदी में मिले इस शव ने न केवल पुलिस बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह एक सामान्य हादसा था, आत्महत्या का मामला है या फिर किसी गहरी साजिश के तहत की गई हत्या। मृतक की पहचान बामनिया खेड़ी निवासी राजेश मालवीय के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब तीस वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद से परिवार सदमे में है और गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

सुबह के समय जब कुछ ग्रामीण रोजमर्रा के काम से पुलिया के पास पहुंचे, तो उन्होंने नीचे नदी के पानी में एक शव को उतराते हुए देखा। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पास जाकर देखने पर स्थिति गंभीर लगी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय स्वयं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शव काफी समय से पानी में पड़ा हुआ हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। शव की स्थिति, नदी का बहाव और पुलिया की ऊंचाई को देखते हुए पुलिस हर संभावित पहलू पर विचार कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं राजेश का संतुलन बिगड़ने से पुलिया से गिरकर हादसे में मौत तो नहीं हुई, या फिर उसने खुद नदी में छलांग लगाकर जान दी। इसके साथ ही पुलिस इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है कि कहीं उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंका तो नहीं गया।

घटनास्थल के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिससे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह बाइक मृतक की ही है या किसी और की। अगर बाइक राजेश की है, तो सवाल यह उठता है कि वह यहां क्यों आया था और किससे मिलने वाला था। वहीं अगर बाइक किसी और की है, तो यह किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा कर सकती है। पुलिस बाइक के नंबर, उसकी हालत और आसपास मिले निशानों की भी जांच कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी बुलाया गया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से मिट्टी, पानी के नमूने और अन्य संभावित साक्ष्य एकत्र किए हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाया जा सके कि मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यही इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है।

मृतक के भाई सोनू मालवीय ने बताया कि राजेश दीपावली के बाद से घर से बाहर रहकर दूसरे स्थान पर काम कर रहा था। वह लंबे समय से गांव नहीं आया था, लेकिन उसका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी होने की जानकारी परिवार को नहीं है। ऐसे में उसका शव घर से करीब 20 किलोमीटर दूर नदी में मिलना परिजनों के लिए बेहद चौंकाने वाला है। परिवार का कहना है कि राजेश शांत स्वभाव का था और अचानक इस तरह उसकी मौत होना समझ से परे है।

पुलिस ने आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले किसी ने राजेश को पुलिया या उसके आसपास देखा था या नहीं। इसके अलावा मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह आखिरी बार किससे बात कर रहा था और उसकी गतिविधियां क्या थीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा।

इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और उत्सुकता का माहौल है। लोग अलग-अलग कयास लगा रहे हैं और हर कोई मौत की असली वजह जानने को लेकर चिंतित है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह मामला हादसे का है, आत्महत्या का है या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। तब तक राजेश मालवीय की मौत शाजापुर जिले के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है।

आस्था पर हमलाः औसानेश्वर मंदिर के गर्भगृह में सेंध, 8 किलो चांदी और नकदी पर हाथ साफ, श्रद्धालुओं में आक्रोश

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित औसानेश्वर मंदिर में मंगलवार देर रात हुई चोरी की वारदात ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिर पूरे इलाके की धार्मिक पहचान माना जाता है। मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात बदमाशों ने मंदिर के गर्भगृह को निशाना बनाते हुए जिस सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया, उसने पुलिस और प्रशासन दोनों को हैरानी में डाल दिया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगे चांदी के छत्र, अरघा में जड़ी चांदी और दान पात्र में रखी नकदी समेत करीब 20 लाख रुपये से अधिक का सामान ले उड़े। बुधवार तड़के जब मंदिर के पुजारी शिवम गिरी रोज की तरह भोर में पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्भगृह का चैनल टूटा हुआ था, ताले क्षत-विक्षत पड़े थे और भीतर भगवान शिव का श्रृंगार अस्त-व्यस्त हालत में था। थोड़ी ही देर में यह खबर आग की तरह फैल गई और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लोगों में गुस्सा, पीड़ा और असमंजस साफ नजर आ रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी, सीओ समीर सिंह और एसडीएम राजेश विश्वकर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी गई।

जांच के दौरान सामने आया कि बदमाशों ने मंदिर के दक्षिणी द्वार को निशाना बनाकर ताला, गेट और चैनल तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली। फुटेज के अनुसार रात करीब ढाई बजे मंकी कैप लगाए एक बदमाश मंदिर परिसर में दाखिल हुआ। उसने बेहद इत्मीनान और धैर्य के साथ पहले प्रवेश किया, फिर मंदिर के मुख्य गेट को अंदर से बंद कर लिया, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति भीतर न आ सके। इसके बाद वह सीधे गर्भगृह तक पहुंचा और लोहे की रॉड की मदद से शिवलिंग के अरघा में जड़ी चांदी को उखाड़ना शुरू कर दिया।

करीब डेढ़ घंटे तक बदमाश गर्भगृह में मौजूद रहा और बिना किसी जल्दबाजी के एक-एक कर चांदी के हिस्सों को निकालता रहा। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर लगा चांदी का छत्र और अरघा में जड़ी करीब आठ किलो चांदी उसने बड़ी सफाई से अलग की। इसके बाद दान पात्र को भी खंगाला गया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई नकदी रखी थी। चोरी के दौरान मंदिर के आसपास कोई हलचल न हो, इसके लिए उसने सभी दरवाजे अंदर से बंद रखे। लगभग चार बजे के आसपास वह उत्तरी द्वार से सामान लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि इतने लंबे समय तक बदमाश मंदिर में मौजूद रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया गया। टीम ने गर्भगृह के भीतर शिवलिंग, अरघा और आसपास के हिस्सों से आधा दर्जन से अधिक उंगलियों के निशान जुटाए हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड की मदद भी ली गई, ताकि बदमाशों की संभावित दिशा और रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान करने की कोशिश में जुटी है और आसपास के इलाकों में लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय गिरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि चोरी गया चांदी का सामान अत्यंत प्राचीन और कीमती था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब औसानेश्वर मंदिर को निशाना बनाया गया हो। करीब दो वर्ष पहले भी मंदिर से स्वर्ण जैसा दिखने वाला तांबे का नाग चोरी हुआ था। बाद में वह नाग जंगल में फेंका हुआ मिला था, लेकिन उस समय मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। अब दूसरी बार इतनी बड़ी चोरी होने से मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी है।

'खेजड़ी के लिए प्राण भी न्योछावर'-बीकानेर की धरती पर जगा पर्यावरणीय चेतना का ज्वालामुखी

(जीएनएस)। राजस्थान के बीकानेर की तपती धरती इन दिनों सिर्फ गर्मी से नहीं, बल्कि खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के संकल्प से भी तप रही है। बीते तीन दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास जमा सैकड़ों साधु-संत, पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज के लोग एक ऐसे आंदोलन को आकार दे रहे हैं, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 'पर्यावरण संघर्ष समिति' के बैनर तले चल रहा यह महापड़ाव अब केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रकृति और विकास के टकराव पर खड़ा एक बड़ा सामाजिक और नैतिक सवाल बन चुका है। आंदोलनकारियों की मांग साफ है—खेजड़ी सहित 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और इसके लिए सख्त कानून तुरंत लागू किया जाए। सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए एमओयू को भी निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है।

तीसरे दिन तक आंदोलन ने और अधिक उग्र और भावनात्मक रूप ले लिया है। आमरण अनशन पर बैठे संतों और पर्यावरण प्रेमियों की संख्या 363 तक पहुंच चुकी है। लगातार अनशन के चलते अब तक पांच लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें आंदोलन स्थल पर ही बनाए गए अस्थायी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की एक टीम दिन-रात तैनात है, लेकिन इसके बावजूद अनशनकारियों के हौसले में कोई कमी नहीं दिख रही। उनके चेहरों पर थकान जरूर है, पर आंखों में खेजड़ी को बचाने का अडिग संकल्प साफ झलकता है।

आंदोलन के केंद्र में खेजड़ी वृक्ष है, जिसे राजस्थान की जीवनरेखा कहा जाता है। यह पेड़ केवल छाया या लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि रेगिस्तान में जीवन का आधार माना जाता है। बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों

को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उसी बलिदान की स्मृति आज फिर बीकानेर की धरती पर जीवित हो उठी है। आंदोलनकारी बार-बार उसी इतिहास का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी उसी राह पर चलने से पीछे नहीं हटेंगे।

संत सच्चिदानंद का कहना है कि सरकार को समझाने के लिए अब कोमल शब्दों का समय बीत चुका है। उनके अनुसार पत्थर को तोड़ने के लिए कठोर होना पड़ता है और सरकार भी उसी पत्थर की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक खेजड़ी और अन्य पुराने पेड़ों को बचाने के लिए ठोस कानून नहीं बनता, तब तक यह अनशन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें। संतों का मानना है कि यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है।

संघर्ष समिति के परसराम बिश्नोई ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हर बार आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन कानून कब बनेगा, इसकी कोई समय-सीमा नहीं बताई जाती। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित और समयबद्ध निर्णय चाहिए। जब तक सरकार स्पष्ट तारीख घोषित नहीं करती, तब तक एक भी अनशनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारियों की भाषा में यह लड़ाई सत्ता से नहीं, बल्कि व्यवस्था की उदासीनता से है।

आंदोलन में शामिल साधु-संतों का कहना है कि यह सनातन मूल्यों की रक्षा का भी प्रश्न है। उनका आरोप है कि जिस सरकार को वे सनातन परंपराओं से जुड़ा मानते थे, वही आज प्रकृति के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक खेजड़ी की अनदेखी कर रही है। भागीरथ तेतरवाल जैसे वक्ता खुले मंच से यह मांग उठा रहे हैं कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक किसी भी परियोजना के नाम पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाए। उनका कहना है कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

आंदोलन का असर अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खेजड़ी की पूजा करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और राजनीति से ऊपर उठकर खेजड़ी व ओरण के संरक्षण की अपील की। उनके इस कदम को आंदोलनकारियों ने नैतिक समर्थन के रूप में देखा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग की है। राजनीतिक समर्थन मिलने से आंदोलनकारियों का मनोबल और बढ़ा है, लेकिन वे साफ कहते हैं कि यह लड़ाई किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि प्रकृति की है।

बीकानेर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बिश्नोई धर्मशाला आंदोलनकारियों से खचाखच भर चुकी है, जिसके चलते कई लोगों को टेंटों में रात गुजारनी पड़ रही है। ठंडी रातों और सीमित सुविधाओं के बावजूद प्रदर्शनकारियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कई लोग पूरी रात जागकर भजन, कीर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संवाद करते नजर आते हैं। यह दृश्य किसी साधारण धरने से ज्यादा एक जन-जागरण की तरह प्रतीत होता है।

एटीएम से राशन की नई व्यवस्था की ओर बिहार पारदर्शिता और तकनीक से बदलेगी पीडीएस

(जीएनएस)। पटना। बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करने जा रही है। राज्य में जल्द ही आम लोगों को एटीएम मशीन की तर्ज पर गेहूं और चावल मिलने लगेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत 'ग्रेन एटीएम' के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी। इस पहल के लागू होने के बाद बिहार देश का चौथा राज्य बन जाएगा, जहां राशन वितरण के लिए एटीएम जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं और शिकायतों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

राज्य की खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने इस योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें ग्रेन एटीएम योजना को लागू करने के लिए सहमति मांगी गई थी। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए

केंद्र को अपनी सहमति भेज दी है। मंत्री के अनुसार, यह योजना गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, राज्य में ग्रेन एटीएम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि मौजूदा राशन वितरण व्यवस्था में कई स्तरों पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं कम तौल देने की बात होती है तो कहीं अनाज की गुणवत्ता और उपलब्धता को लेकर सवाल उठते हैं। कई बार उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल पाता, जिससे उनमें असंतोष पैदा होता है। ग्रेन एटीएम के जरिए इन समस्याओं को काफी हद तक दूर करने की योजना है। मशीन में पहले से तय मानकों के अनुसार अनाज रखा जाएगा और उपभोक्ता की पहचान सत्यापित होने के बाद उतनी ही मात्रा में अनाज निकलेगा, जितना उसका अधिकार है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और गड़बड़ियों की गुंजाइश भी घटेगी।

लेसी सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार राशन कार्ड धारकों के हित में लगातार नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। अभी पीओएस मशीन के जरिए अंगूठा लगाकर राशन देने की व्यवस्था लागू है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाज सही व्यक्ति तक पहुंचे। अब विभाग इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पीओएस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके माध्यम से अनाज को डिजिटल तरीके से तौला जाएगा, जिससे कम तौल या हेराफेरी की शिकायतों पर लगाम लगेगी। उपभोक्ताओं को विश्वास होगा कि उन्हें उनका पूरा हक मिल रहा है।

सरकारी स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि ग्रेन एटीएम जैसी योजनाएं भविष्य की जरूरत हैं। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में एटीएम ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया, उसी तरह राशन व्यवस्था में यह तकनीकी बदलाव भी सुविधा और भरोसे का प्रतीक बन सकता है। खासकर शहरी इलाकों में, जहां लोग समय की कमी के कारण राशन दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े नहीं हो पाते, वहां यह व्यवस्था काफी कारगर साबित हो सकती है। तय समय पर मशीन से अनाज मिलने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उनकी निर्भरता बिचौलियों पर कम होगी।

सरकार को उम्मीद है कि पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इस योजना के व्यावहारिक पहलुओं का आकलन किया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इससे न केवल बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिक बनेगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में सामने आएगी।

उत्तर प्रदेश का बजट सत्रः विकास बहस और दिशा तय करने वाले 12 दिन

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने वाला विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर फरवरी माह में शुरू होने जा रहा है। 9 से 20 फरवरी तक चलने वाला यह सत्र न केवल राज्य सरकार के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। यह बजट आने वाले वर्ष में विकास की प्राथमिकताओं, सरकार की नीतिगत सोच और आर्थिक रणनीति को स्पष्ट रूप से सामने लाएगा। लखनऊ में प्रस्तावित इस सत्र को लेकर राजनीतिक हलकों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम को अनंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। आम तौर पर यह प्रक्रिया औपचारिक होती है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बजट सत्र हमेशा से ही विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार अपने कामकाज का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है और विपक्ष को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा मंच मिलता है।

सत्र की शुरुआत 9 फरवरी को होगी, जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यपाल का अभिभाषण परंपरागत रूप से सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत करता है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार बीते समय में किन क्षेत्रों में आगे बढ़ी और आने वाले वर्ष में किन मुद्दों को प्राथमिकता देने जा रही है। इस अभिभाषण को सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यही आगे की बहस और चर्चा की दिशा तय करता है।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार की ओर से कुछ अध्यादेश और विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कुछ अहम नीतिगत या प्रशासनिक फैसलों को विधायी रूप देने की तैयारी में है। अक्सर ऐसे विधेयक विकास, कानून-व्यवस्था, सामाजिक कल्याण या आर्थिक सुधारों से जुड़े होते हैं, जिन पर बाद में विस्तृत चर्चा होती है। विपक्ष आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार की नीतियों का औपचारिक प्रचार मानते हुए उस पर तीखे सवाल उठाता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धियों का प्रमाण बताता है।

10 फरवरी का दिन सदन के लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन निधन के निर्देश पढ़े जाएंगे और दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल और सोनभद्र के दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह गोंड के निधन पर सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह अवसर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं और मानवीय संवेदनाओं को सम्मान देने का होता है। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित रहेगी, जिससे बजट से पहले सभी दल अपनी रणनीति को और पुख्ता कर सकें।

इस बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन 11 फरवरी माना जा रहा है, जब प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बजट भाषण हमेशा से ही सदन और जनता दोनों की निगाहों में रहता है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति, राजस्व अनुमान, खर्च की प्राथमिकताएं और विकास योजनाओं की झलक मिलती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बजट का सीधा असर किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर पड़ता है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो शुक्रवार तक चलेगी। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करेगा, जबकि विपक्ष बजट और सरकार की प्राथमिकताओं में कमियों को उजागर करने की कोशिश करेगा। यह बहस लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है और जनता के मुद्दे सदन के पटल पर आते हैं। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा, लेकिन इसके बाद 16 फरवरी से बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी।

सोना-चांदी में तेजी जारीः सोना वायदा में 4932 रुपये और चांदी वायदा में 15784 रुपये का अधिक ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 133808.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 42166.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 91639.43 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 40400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3548.05 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 35850.83 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158420 रुपये के भाव पर खूलकर, 160755 रुपये के दिन के उच्च और 156553 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153809 रुपये के पिछले बंद के सामने 4932 रुपये या 3.21 फीसदी की मजबूती के साथ 158741 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 3842 रुपये या 3.03 फीसदी बढ़कर 130682 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 510 रुपये या 3.23 फीसदी बढ़कर 16305 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मार्च वायदा 152849 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158664 रुपये और नीचे में 152849 रुपये पर पहुंचकर, 4863 रुपये या 3.2 फीसदी बढ़कर 156725 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 157270 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163000 रुपये और नीचे में 152168 रुपये पर पहुंचकर, 155897 रुपये के पिछले बंद के सामने 5418 रुपये या 3.48 फीसदी बढ़कर 161315 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 278015 रुपये के भाव पर खूलकर, 286306 रुपये के दिन के उच्च और 275044 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268015 रुपये के पिछले बंद के सामने 15784 रुपये या 5.89 फीसदी की बढ़त के साथ 283799 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 15298 रुपये या 5.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 291596 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 15340 रुपये या 5.55 फीसदी की तेजी के संग 291763 रुपये प्रति किलो हुआ।

क्रूड ऑयल वायदा में 39 रुपये की वृद्धि : कमोडिटी वायदाओं में 42166.14 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 91639.43 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 35850.83 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40400 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 4205.44 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.02 फीसदी टूटकर 1282.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.6 रुपये या 0.49 फीसदी की बढ़त के साथ 325.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 65 पैसे या 0.21 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 315.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी घटकर 191.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1992.01 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5764 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5796 रुपये और नीचे में 5695 रुपये पर पहुंचकर, 39 रुपये या 0.68 फीसदी बढ़कर 5748 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 41 रुपये या 0.72 फीसदी की मजबूती के साथ 5751 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 301.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 305.6 रुपये के दिन के उच्च और 295.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 301.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.3 रुपये या 0.76 फीसदी की बढ़त के साथ 303.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 2.2 रुपये या 0.73 फीसदी बढ़कर 304 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 987 रुपये पर खूलकर, बिना बदलाव के 980.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20975.34 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14875.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3758.58 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 158.46 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 26.57 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 256.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 870.31 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1108.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.91 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9535 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68827 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 30701 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 406959 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 49247 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9242 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22641 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62870 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16959 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 16047 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 39903 पॉइंट पर खूलकर, 41190 के उच्च और 39903 के नीचले स्तर को छूकर, 1385 पॉइंट बढ़कर 40400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.1 रुपये की बढ़त के साथ 202.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 30.45 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1784.5 रुपये की बढ़त के साथ 9180 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6570 रुपये की बढ़त के साथ 27500.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.93 रुपये की गिरावट के साथ 57 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.13 रुपये की गिरावट के साथ 3.99 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.2 रुपये की गिरावट के साथ 198.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे के सुधार के साथ 26.9 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1045 रुपये की गिरावट के साथ 3067.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1845.5 रुपये की गिरावट के साथ 4378 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 59 पैसे की नरमी के साथ 26.54 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 72 पैसे की नरमी के साथ 10.5 रुपये हुआ।